गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 075
दि. 14.07.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

रेल सफर में बढ़ी बेडरोल चोरी की समस्या, चार वर्षों में 1.27 करोड़ चादरें, तौलिये और कंबल गायब, करोड़ों का आर्थिक नुकसान

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की एसी ट्रेनों में यात्रियों को सफर के दौरान दी जाने वाली मुफ्त बेडरोल सुविधा अब रेलवे और इससे जुड़े सेवा प्रदाताओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सामने आए आंकड़ों ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच देशभर की एसी ट्रेनों से 1.27 करोड़ से अधिक बेडरोल आइटम गायब हो चुके हैं। इनमें फेस टावल, चादरें, तकिए के कवर, कंबल और तकिए शामिल हैं। इन चोरी या गायब हुए सामान के कारण बेडरोल आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों को 104.51 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, हर हजार यात्रियों में औसतन एक यात्री सफर समाप्त होने के बाद रेलवे का कोई न कोई बेडरोल सामान अपने साथ ले जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लापरवाही और जिम्मेदारी की कमी को भी दर्शाता है।

भारतीय रेलवे प्रतिदिन लाखों यात्रियों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराता है। लंबी दूरी की एसी ट्रेनों में सफर करने वाले लगभग आठ लाख यात्रियों को रेलवे की ओर से मुफ्त बेडरोल उपलब्ध कराया जाता है। इस किट में सामान्यतः दो साफ चादरें, एक कंबल, एक तकिया, तकिए का कवर और एक फेस टावल दिया जाता है। यात्रा समाप्त होने पर इन सभी वस्तुओं को वापस लेना रेलवे की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में यात्री इन वस्तुओं को अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसके कारण रेलवे की व्यवस्था पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक चोरी फेस टावल की हुई है। पिछले चार वर्षों में 46.54 लाख फेस टावल गायब हुए हैं। इसके बाद 41.13 लाख चादरें, 23.59 लाख तकिए के कवर, 12.95 लाख कंबल और 2.76 लाख तकिए लापता पाए गए। आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्ष 2022 की तुलना में 2025 तक ऐसी घटनाओं में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

इससे स्पष्ट है कि समस्या लगातार बढ़ रही है और अब यह रेलवे प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि देश के कुछ रेलवे मंडलों में यह समस्या अधिक गंभीर है। सात रेलवे जोन के 10 प्रमुख डिवीजनों में कुल चोरी का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया। सबसे अधिक 25.76 लाख बेडरोल आइटम बीकानेर मंडल से गायब हुए। इसके बाद रांची, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, अहमदाबाद और दानापुर मंडलों का स्थान रहा। इसके विपरीत तिरुचिरापल्ली और पलक्कड़ मंडलों में इस तरह की चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि बेहतर निगरानी और प्रभावी प्रबंधन से इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

इन चोरी की घटनाओं का सबसे बड़ा असर बेडरोल आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों और कोच अटेंडेंट पर पड़ता है। रेलवे बोर्ड की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यदि कोई बेडरोल सामान गायब होता है, तो उसकी कीमत पहले संबंधित ठेकेदार से वसूली जाती है। इसके बाद कई मामलों में यही राशि कोच अटेंडेंट या संबंधित कर्मचारियों के वेतन से काट ली जाती है। कई कर्मचारियों ने बताया कि हर महीने उनके वेतन से दो हजार से तीन हजार रुपये तक काट लिए जाते हैं, जबकि उनकी दैनिक मजदूरी लगभग 700 रुपये के आसपास होती है। ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति की चोरी का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ उन कर्मचारियों पर पड़ता है, जिनका इस चोरी से प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं होता।

रेलवे से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बेडरोल वितरण और संग्रहण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्रियों को सीलबंद पैक में बेडरोल उपलब्ध कराया जाता है और यात्रा समाप्त होने से पहले कोच अटेंडेंट इन्हें वापस एकत्र करते हैं। हालांकि कई यात्री स्टेशन पर उतरते समय जल्दबाजी में या जानबूझकर कुछ सामान अपने साथ ले जाते हैं। कई बार अटेंडेंट भी भीड़भाड़ और सीमित समय के कारण प्रत्येक यात्री से सामान वापस लेने में सफल नहीं हो पाते।

रेलवे मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय का कहना है कि अभी तक किसी कर्मचारी की मिलीभगत का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। इसके बावजूद व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे ने कोचों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने, कोच मित्र ऐप के माध्यम से शिकायतों की निगरानी, कर्मचारियों की नियमित काउंसलिंग, ठेकेदार कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन तथा यात्रियों से गंतव्य स्टेशन पहुंचने से लगभग 30 मिनट पहले बेडरोल वापस लेने जैसी व्यवस्थाएं लागू की हैं। इसके अलावा यात्रियों को भी समय-समय पर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे जैसी विशाल सार्वजनिक सेवा प्रणाली में छोटी-छोटी लापरवाहियां भी करोड़ों रुपये के नुकसान का कारण बन सकती हैं। यदि हर दिन कुछ ही यात्री एक तौलिया, चादर या तकिया अपने साथ ले जाते हैं, तो वर्षभर में यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इन वस्तुओं की बार-बार खरीद, धुलाई, परिवहन और वितरण पर पहले से ही रेलवे का बड़ा खर्च होता है। ऐसे में चोरी की घटनाएं इस खर्च को और बढ़ा देती हैं, जिसका अप्रत्यक्ष असर रेलवे की परिचालन लागत पर पड़ता है।

आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेलवे के 54 मंडलों से आंकड़े उपलब्ध कराए गए, जबकि कुछ मंडलों ने पूरी जानकारी साझा नहीं की। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि वास्तविक नुकसान 104.51 करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकता है। यदि सभी मंडलों के पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हों, तो चोरी की कुल संख्या और आर्थिक नुकसान दोनों में वृद्धि हो सकती है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को यह समझना होगा कि बेडरोल किट उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुविधा का हिस्सा है। इन्हें यात्रा समाप्त होने पर वापस करना प्रत्येक यात्री की जिम्मेदारी है। यदि इस प्रकार की चोरी या लापरवाही जारी रहती है, तो इसका सीधा असर भविष्य में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता और लागत पर पड़ सकता है।

रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सफर को अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी निगरानी के साथ-साथ यात्रियों में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। यदि यात्री जिम्मेदारी का परिचय दें और रेलवे की संपत्ति को अपनी सामूहिक धरोहर समझें, तो इस तरह की चोरी की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इससे न केवल करोड़ों रुपये की बचत होगी, बल्कि कर्मचारियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सूरत में बाढ़ का कहरः व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 42 करोड़ रुपये का नुकसान, राहत और मुआवजे की मांग तेज, पुलिस ने शुरू की जांच

सूरत। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने गुजरात के औद्योगिक एवं व्यापारिक शहर सूरत में बड़े पैमाने पर आर्थिक तबाही मचाई है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल वराछा के प्रमुख व्यापारिक केंद्र पोद्दार आर्केड और यश प्लाजा में सैकड़ों दुकानों में बारिश का पानी भर जाने से करोड़ों रुपये का माल, फर्नीचर, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और व्यावसायिक दस्तावेज नष्ट हो गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार दोनों परिसरों में करीब 42 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस भारी क्षति के बाद व्यापारियों ने सामूहिक रूप से वराछा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और राज्य सरकार से विशेष राहत पैकेज तथा आर्थिक सहायता की मांग की है।

व्यापारियों के अनुसार भारी बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से बड़ी मात्रा में पानी व्यापारिक परिसरों के बेसमेंट और निचली मंजिलों में घुस गया। कई दुकानों में कुछ ही मिनटों में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां रखा तैयार माल, कच्चा माल, फर्नीचर, कंप्यूटर, सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और अन्य व्यावसायिक सामग्री पूरी तरह खराब हो गई। अनेक व्यापारियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार एक ही दिन में गंभीर संकट में पहुंच गया।

प्राथमिक आकलन के अनुसार पोद्दार आर्केड में लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि यश प्लाजा में करीब 7 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार दोनों व्यापारिक परिसरों में कुल मिलाकर लगभग 42 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि विस्तृत सर्वेक्षण और पंचनामा पूरा होने के बाद वास्तविक नुकसान का अंतिम आकलन किया जाएगा।

नुकसान की गंभीरता को देखते हुए व्यापारियों ने वराछा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर मामले से संबंधित जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत का उद्देश्य नुकसान का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि भविष्य में बीमा दावों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में व्यापारियों को आवश्यक सहायता मिल सके।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों ने व्यापारियों से बातचीत कर नुकसान का जायजा लिया और प्रत्येक प्रभावित दुकान का अलग-अलग पंचनामा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासन का कहना है कि विस्तृत दस्तावेजीकरण से भविष्य में बीमा कंपनियों और सरकारी सहायता योजनाओं के तहत राहत दिलाने में सुविधा होगी।

अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक दुकान में हुए नुकसान का अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें नष्ट हुए माल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और अन्य संपत्तियों का विवरण दर्ज किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित व्यापारियों को प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग वे बीमा दावों अथवा अन्य राहत प्रक्रियाओं में कर सकेंगे।

यश प्लाजा के व्यापारी प्रतिनिधि महेश गढ़िया ने कहा कि इस आपदा ने बड़ी संख्या में व्यापारियों को आर्थिक रूप से झकझोर दिया है। उन्होंने बताया कि कई व्यापारियों की वर्षों की जमा पूंजी एक ही घटना में नष्ट हो गई। हालांकि इस कठिन समय में व्यापारिक समुदाय, मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग उनका मनोबल बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रत्येक नुकसान का सही दस्तावेजीकरण करना है, ताकि आगे बीमा और सरकारी सहायता की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

व्यापारियों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित अधिकांश कारोबारी छोटे और मध्यम वर्ग से जुड़े हैं, जिनके लिए इतना बड़ा आर्थिक नुकसान अपने दम पर वहन करना आसान नहीं है। कई दुकानदारों के सामने अब कारोबार दोबारा शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है। माल नष्ट होने के साथ-साथ कई स्थानों पर फर्नीचर, कंप्यूटर, बिजली की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

सरकार गिराने के आरोप पर सियासी टकराव तेज, भाजपा ने उमर अब्दुल्ला को भेजा 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस

जम्मू। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उनकी सरकार गिराने की कथित कोशिश का आरोप लगाए जाने के बाद विवाद कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजते हुए उनके बयान को पूरी तरह झूठा, निराधार और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। पार्टी ने नोटिस के माध्यम से सात दिनों के भीतर आरोप वापस लेने और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सिविल और आपराधिक मानहानि की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

भाजपा का यह कदम उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को नकद धनराशि और मंत्री पद का लालच देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार को गिराने के लिए राजनीतिक खरीद-फरोख्त की कोशिश की गई, लेकिन उनके विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे और ऐसी किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोपों को पूरी तरह असत्य और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। पार्टी का कहना है कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के लगाए गए ऐसे आरोप न केवल भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं।

भाजपा की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका समर्थन करने के लिए उनके पास कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी राजनीतिक दल या उसके नेताओं पर विधायकों की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो उनके समर्थन में ठोस प्रमाण होना आवश्यक है। बिना साक्ष्य के ऐसे बयान देना मानहानिकारक है और इससे पार्टी की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है।

नोटिस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे सात दिनों के भीतर अपने बयान को लिखित रूप में वापस लें और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो भाजपा उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने का मानहानि मुकदमा दायर करेगी। इसके साथ ही भारतीय कानून के तहत उपलब्ध अन्य सिविल और आपराधिक कानूनी विकल्पों का भी सहारा लिया जाएगा।

भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन बिना किसी आधार के लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने और जनता के बीच भ्रम फैलाने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं।

दूसरी ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अभी तक भाजपा के कानूनी नोटिस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और अधिक गहरा सकता है, क्योंकि मामला अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का रूप भी ले चुका है।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में पिछले कुछ समय से विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की स्थिरता, विधायकों की निष्ठा और राजनीतिक रणनीतियों को लेकर समय-समय पर कई दावे और प्रतिदावे सामने आते रहे हैं। ऐसे माहौल में भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। यदि वे अपने बयान पर कायम रहते हैं, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जबकि आरोप वापस लेने या माफी मांगने की स्थिति में यह विवाद अलग दिशा ले सकता है। फिलहाल इस घटनाक्रम ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक असर पर भी नजर रहेगी।

पड़ोसी राज्य में कोरोना से मौतों के बाद ओडिशा सतर्क अस्पतालों में बढ़ाई निगरानी, जांच और तैयारियां तेज

भुवनेश्वर। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण से दो मरीजों की मौत के बाद ओडिशा सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। राज्य सरकार ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है, जबकि सरकारी और निजी अस्पतालों को संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी राज्य की स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार आंध्र प्रदेश में हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण दो मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इनमें से एक मामला कडप्पा जिले का बताया गया है, जहां 9 जुलाई को 46 वर्षीय एक व्यक्ति की संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। मरीज को कई दिनों से तेज खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अन्य श्वसन संबंधी लक्षण थे। चिकित्सकों ने उपचार का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दूसरी मौत की पुष्टि के बाद आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी निगरानी और तैयारियां बढ़ा दी हैं।

इन घटनाओं के बाद ओडिशा सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच बड़ी संख्या में लोगों का रोजाना आवागमन होता है। व्यापार, रोजगार, शिक्षा और अन्य कारणों से हजारों लोग दोनों राज्यों के बीच यात्रा करते हैं। ऐसे में यदि संक्रमण फैलता है तो सीमावर्ती जिलों पर इसका असर पड़ सकता है। इसी संभावना को ध्यान

में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीमा से लगे इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

ओडिशा के स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवींद्रनाथ मिश्रा ने कहा कि फिलहाल राज्य में घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी के मामले में सावधानी ही सबसे प्रभावी उपाय है। इसलिए सरकार हर स्तर पर निगरानी रख रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह तैयार रखा गया है।

राज्य सरकार ने सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन को कहा गया है कि यदि किसी मरीज में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई या कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसकी तुरंत जांच कराई जाए। संदिग्ध मरीजों की पहचान होते ही आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा ताकि संक्रमण फैलने की संभावना को रोका जा सके।

स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच की गति भी बढ़ा दी है। विशेष रूप से उन लोगों की जांच पर जोर दिया जा रहा है जो हाल ही में आंध्र प्रदेश या अन्य प्रभावित क्षेत्रों से लौटे हैं अथवा जिनमें संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्रयोगशालाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित मामले का तुरंत पता लगाया जा सके।

अस्पतालों के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत आइसोलेशन वार्डों को तैयार रखने, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन आपूर्ति की नियमित समीक्षा करने और गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण नियंत्रण संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण रोकथाम और मरीजों की निगरानी पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी अस्पताल में कोरोना का संदिग्ध मरीज भर्ती होता है तो उसकी जानकारी तुरंत जिला स्वास्थ्य प्रशासन और राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जाए। इससे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी और संपर्क में आए लोगों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।

राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। विभिन्न जिलों से रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो अतिरिक्त चिकित्सा दल और संसाधन भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से मिले अनुभव के आधार पर इस बार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से बेहतर तैयारी की गई है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि यदि उन्हें बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में कठिनाई या अन्य श्वसन संबंधी लक्षण महसूस हों तो स्वयं इलाज करने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और समय-समय पर इसके नए मामले सामने आते रहते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर मास्क का उपयोग करना, हाथों की नियमित सफाई और भीड़भाड़ वाले स्थानों में सावधानी बरतना आज भी महत्वपूर्ण है। संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर दूसरों के संपर्क में आने से बचना भी आवश्यक है।

ओडिशा सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और केंद्र सरकार तथा पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय कर आवश्यक कदम उठा रहा है। सरकार का मानना है कि समय रहते की गई सतर्कता और प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन से किसी भी संभावित संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। यही कारण है कि राज्य में निगरानी, जांच और अस्पतालों की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।

संपादकीय

ज़हरीली विरासत

शासन-प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद आज भी पंजाब की नदियों को जहरीला बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसकी पुष्टि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्वीकृति है कि आज भी आठ सौ से अधिक प्रदूषण के स्रोत राज्य की नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। निश्चय ही यह तथ्य उन विभागों व संस्थाओं के कामकाज पर सवालिया निशान है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन से जुड़े हैं। साथ ही लंबे समय से अदालत के हस्तक्षेप व विभिन्न सर्वेक्षणों में सामने आए तथ्यों की पुष्टि होती है कि राज्य में जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई न होने से उपजा संकट है। वर्षों से सरकारें एक्शन प्लान बनाने के दावे करती रही हैं। कभी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात होती है तो कभी कमेटियां बनाने के दावे होते हैं। आखिर क्यों आज भी बिना साफ किया हुआ सीवेज और औद्योगिक कचरा सतलुज,ब्यास और इनकी सहायक नदियों में बदस्तूर बहाया जा रहा है। जाहिर है, मौजूदा संसाधनों का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है या उनका रखरखाव ठीक नहीं है। फलतः जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा संकट पैदा होता है। जो धीरे-धीरे आपदा का रूप ले लेता है। आज फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों के जरिये भारी धातुएं और जहरीले तत्व भूजल को प्रदूषित करने के बाद, हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। जो राज्य के बहुचर्चित ' कैंसर बेल्ट' के रूप में हमारे सामने मौजूद है।

निस्संदेह, पंजाब में यदि हरित क्रांति का परचम लहराया तो उसके मूल में पंजाब की नदियों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज वे तंत्र की काहिली, अनियोजित शहरीकरण, नियम-कानूनों का क्रियान्वयन न होने और दोषियों को सजा न मिलने का दंड चुका रही हैं। एनजीटी गाहे-बगाहे नगर निकायों की शिथिलता दर्शाकर सच्चाई से आम लोगों को अवगत कराता रहा है। निस्संदेह, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि इसकी जिम्मेदारी तय न की जाए और सख्त जुर्माना लगाना पर्यावरण संरक्षण नीति का हिस्सा नहीं बनता है। राज्य ने साबित किया है कि मरणासन्न नदियों को फिर से जीवित किया जा सकता है। काली बेईं को पुनर्जीवित करने में जागरूक लोगों की बड़ी भूमिका रही है। जो दर्शाता है कि पक्के इरादे के साथ किए गये प्रयास से बेहद बुरे हालात में पहुंच चुके जल स्रोत को भी जीवंत बनाया जा सकता है। लेकिन इक्का-दुक्का सफलताएं ही व्यापक रणनीति की जगह नहीं ले सकतीं। जरूरी है कि नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए, सार्वजनिक रिपोर्टिंग को पारदर्शी बनाएं तथा सीवेज एवं कचरा-शोधन प्रणालियों में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। सर्वविदित है कि पंजाब का नाम यहां की नदियों से पड़ा है। ऐसे में इन नदियों को खुले नाले बनते रहने देने से न केवल हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र व लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि राज्य की खुशहाली व पहचान के लिये भी एक खतरा है। अब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का वक्त है।

स्याह दौर को याद करके उबरने का समय

हालिया दो फिल्में 'मैं वापस आऊंगा' और 'सतलुज' पंजाब की स्मृतियों में दबे जख्मों को सामने लाती हैं। एक दास्तान में देश विभाजन के घावों की टीस है तो दूसरी में आतंक के दौर के आघातों का सामूहिक संताप। बेशक, सभी पहलू सामने लाने व समाधान पर चर्चा हो।

पिछले कुछ हफ़्तों से ज़िंदगी, दो कलाकृतियों में उतरने की कोशिश कर रही है, यह समझने के लिए कि दशकों पहले क्या हुआ। इम्तियाज़ अली की 1947 में देश के विभाजन पर बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा', जो 80 साल पीछे जाकर उन लोगों की कहानी बताती है, जिन्हें एक घर से दूसरे घर की तलाश में खुद की जड़ें उखाड़ने को मजबूर किया गया था, सदा के लिए 'रिफ्यूजी' का ठप्पा लेकर - लाहौर में छोड़े गए मॉडल टाउन की याद में दिल्ली के बाहरी इलाके में उसकी नकल कर बनाए मॉडल टाउन में बसना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफी दूर है; लायलपुर नाम के शहर में अपने घर की याद में, जो अब है ही नहीं, जालंधर में बनाए लायलपुर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल जैसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना। लायलपुर का नया नाम पिछले कुछ सालों से फैसलाबाद हो गया है, लेकिन जालंधर में लोगों को कौन समझाए। याद्दाश्त के साथ यही समस्या है- आपने जो अपनी आंखों से देखा हो, वह ओझल नहीं हो पाता या जो सुनी थीं, वह आवाज़ें भुलाए नहीं भूलतीं। भले ही आप उसे व्यक्तिगत रूप से देख या सुन नहीं सकते हों, लेकिन विगत की यादें असहज दुःस्वपन बनाने के लिए काफी होती हैं। चंडीगढ़ में मेरे मित्र अपने माता-पिता को 'मैं वापस आऊंगा' दिखाने से कतरा रहे हैं, कि कहीं ऐसा न हो कि वे उस आघात को पुनः जीएं, जिससे वे गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब आघातों से अपरिचित है। 'बदला और सुलह' यह दो भाव, जैसा कि राजमोहन गांधी ने इसी नाम की अपनी किताब में बहुत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, पंजाब में इनकी गूंज दशकों, यहां तक कि सदियों तक रही है। यदि दिल्ली 'सोने की चिड़िया' किसी लुटेरे की महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है, तो उस तक पहुंचने का रास्ता पंजाब से होकर है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पंजाब की सभी नदियों को पार करना पड़ता था। कुछ को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले

ही रोक लिया गया, इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय है ईसा पूर्व 326 में सिकंदर का विश्व विजय अभियान रथ रोक देना – पंजाब में रोके जाने के बाद उसे उल्टी दिशा पकड़नी पड़ी और वापस लौट गया। यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नाम के साथ 'द' आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। इस बीच, समय की धारा अपने साथ, इसकी नदियों की भांति, हमलावरों, घुसपैठियों, लोकतंत्रवादियों, हत्यारों, आतंकवादियों, सशस्त्र विद्रोहियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बहाती चली गया- यह सूची अंतहीन है, जिसमें हर किस्म के चाहे-अनचाहे पाप शामिल हैं।

इन दिनों, जबकि मॉनसून पूरे देश में छा चुका है, हमारी नदियां उफान पर हैं। चिनाब, जिसे आज भी पंजाब की नदी कहा जाता है, हालांकि यह 1947 के बाद से भारतीय पंजाब की सीमा से परे बहती है, पाकिस्तानी पंजाब में घुसने से पहले जम्मू इलाके में अपने किनारों पर दहाड़ती है — आप इसके बहाव को रोक नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हो या बाद में, भूगोल राजनीति का गुलाम नहीं हो सकता।

चिनाब की बात की जाए तो, सतलुज का जिक्र कैसे छूट सकता है-यहां नदी नहीं, फिल्म की बात है। पूरे पंजाब ने इसे देख लिया है, या देख रहा है- गांव की कमेटियों द्वारा लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर, किसी गुरुद्वारे के साए में या खुले मैदान में, शाम ढलने के बाद, केंद्र द्वारा लगाया प्रतिबंध नजरअंदाज करते हुए। यहां तक कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भी राजधानी के बीचोंबीच इसके शो चला रही है। यह अजीब विडंबना है। हर राजनीतिक दल सावधानीपूर्वक निगाह रखे हुए है, क्योंकि चुनाव में मुश्किल से छह माह बचे हैं, उनमें से हर कोई अच्छी तरह जानता है कि अगर वे सही बात नहीं कहेंगे, या सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वे राज्य में चल रही भावनाओं की लहर में बह सकते हैं। 'द ट्रिब्यून' में मेरे हर सहयोगी का कहना है कि 'हर कोई सब कुछ जानता है, उन सालों में क्या हुआ था'। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? सतलुज में ऐसा क्या है जिसने पंजाब की संवेदनाओं को छू दिया है? क्या केंद्र सरकार के प्रतिबंध का सच में मतलब है कि यह बहुत जल्दबाजी में लिया निर्णय है, कि पंजाब को अपनी भयावहता को देखने के लिए कुछ और दशक चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 'मैं वापस आऊंगा' ने 80 साल बाद किया है, और यह कि अंधियारे को न छेड़ना ही बेहतर है, चुनौती देना तो दूर की बात। आखिर, सच तो यह कि दिलजीत दोसांझ 'पिंड' में अपने घर नहीं, बल्कि 'अमेरिका' में रहते हैं। डर यह है कि पंजाब में फिर से कहीं दरार पैदा न हो जाए। लोग दो पक्षों में बंट जाएंगे। यह आलोचना कि फिल्म 'बहुत ज़्यादा एकतरफ़ा' है, इसका असल में मतलब है कि सिर्फ़ एक पक्ष, मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का पक्ष ही सामने रखा गया है। यह नहीं कि कैसे आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों, हिंदू और सिख, दोनों को मार डाला। यह नहीं कि कैसे पंजाब पुलिस के जवानों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया और उनके परिवारों को कितनी तकलीफ़ हुई। कैसे हिंदुओं को भुगतना पड़ा। यह भी नहीं कि कैसे आस्थावान हिंदुओं और सिखों ने सामना किया। निश्चित रूप से यह भी नहीं दिखाया कि कैसे पाकिस्तान ने पंजाब में पहले से जल रही आग को और भड़काया। सच तो यह है कि फिल्म सतलुज ने सतह को खरोंच दिया है, एक स्याह, बदसूरत पक्ष उघाड़ते हुए- यह अभी साफ़ नहीं कि लोग इसे कैसे लेंगे। फिल्म में खालड़ा के हवाले से कहा गया है कि 25,000 बेगुनाह लोग मारे गए थे। साल 2019 में द ट्रिब्यून में लिखते हुए, सुरक्षा विश्लेषक और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल के रिश्तेदार, अजय साहनी ने बताया है कि 1981 और 1995 के बीच-जिस साल तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और खालड़ा दोनों मारे गए थे—11,696 आम लोग और सुरक्षा बलों के 1,746 जवान (पंजाब पुलिस के 1,415) आतंकवादियों ने मारे, जबकि पुलिस ने 8,090 आतंकवादियों को मार गिराया। यानी कुल 21,532 लोग। इस बीच, सोशल मीडिया दावों और जवाबी-दावों से भरा हुआ है, आवाज़ और गुस्से, दोनों के जरिए। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू का एक्स हैंडल उस समय की ब्लैक-एंड-व्हाइट वीडियो से भरा पड़ा है, जिसमें क्लीन-शेव मृत लोग दिख रहे हैं- किसी का भी चेहरा ढका नहीं है। आप सही में ये सवाल पूछ सकते हैंः ये वीडियो अब क्यों सामने लाये जा रहे, और उन्हें सोशल मीडिया के सख्त सेंसर से कैसे बचने दिया जा रहा? लेकिन जब बिट्टू ने मेरी सहयोगी शिवानी भाकू से कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध भाजपा ने नहीं लगाया। तो शायद उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश नहीं देखा है।

पिछले हफ़्ते इस अख़बार के एक संपादकीय का शीर्षक था, 'सतलुज को बहने दो', जिसमें कहा गया था कि पंजाब के सामूहिक संताप तभी कम हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लेखक, फिल्म निर्माता, मीडिया, सब लोग– इस बारे बात करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और शायद क्यों हुआ। सामूहिक संत्रास पर मरहम रूपी सामूहिक शोक की ज़रूरत होती है– न कि किसी पर उंगली उठाना या नाम लेना, या दोषरोपण करना। न तो कांग्रेस, न ही अकाली दल या भाजपा (जब वह अकाली दल के साथ गठबंधन में थी) ने सत्ता में रहने के दौरान इस दिशा में कुछ खास किया है। 'मैं वापस आऊंगा' देखने में 80 साल गए, इस बीच वह पीढ़ी गुज़र गई और यह आज भी आंसू ला देने वाली फ़िल्म है। 112 साल हो गए हैं जब पंजाब ने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने के लिए पांच लाख लोग भेजे थे — रविवार को, द ट्रिब्यून में लेख है कि कैसे उनमें से 9,909, जिन्हें भुला दिया गया था और इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया था, आखिरकार उनकी शहादत को मान्यता मिली। पंजाब में आतंकवाद खत्म हुए लगभग 30 साल हो गए - अपने बुरे अतीत को भूलने या नकारने के लिए नहीं, बल्कि याद करने और जख्म भरने के लिए हमें पहला कदम उठाना चाहिए। और वह वक्त यही है।

प्रेरणा

सच्ची समृद्धि की पहचान: बुद्धिमत्ता का सबसे अनमोल उत्तर

धन और ज्ञान के महत्व पर सदियों से चर्चा होती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि धन के बिना जीवन अधूरा है, जबकि कुछ का विश्वास है कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। वास्तव में ये दोनों ही जीवन के आवश्यक स्तंभ हैं, लेकिन इनका सही मूल्य तभी समझ आता है जब व्यक्ति के भीतर विवेक, आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण हो। इतिहास में अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता केवल पुस्तकीय ज्ञान या अपार संपत्ति से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। स्वामी विवेकानंद का छात्र जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग इसी सत्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यह केवल एक प्रश्न और उत्तर की घटना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और तार्किक सोच का ऐसा उदाहरण है, जो आज भी हर विद्यार्थी, शिक्षक और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद, जिन्हें उस समय नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बचपन से ही नरेंद्र असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी और किसी भी विषय को गहराई से समझने की उनकी क्षमता उन्हें अपने साथियों से अलग पहचान दिलाती थी। वे केवल किताबों तक सीमित विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि हर विषय को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखने में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि उनके शिक्षक भी उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित रहते थे, हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उनकी प्रतिभा स्वीकार नहीं थी। कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, जो भारतीय विद्यार्थियों को स्वयं से कम समझते थे। उनके मन में यह पूर्वाग्रह था कि भारतीय छात्र चाहे जितनी मेहनत कर लें, वे अंग्रेजों जैसी बुद्धिमत्ता नहीं रख सकते। नरेंद्र की तीव्र बुद्धि और हर प्रश्न का सटीक उत्तर देने की क्षमता उन्हें भीतर ही भीतर असहज कर देती थी। कई बार कक्षा में ऐसी स्थिति बन जाती कि प्रोफेसर का तर्क कमजोर पड़ जाता और नरेंद्र के विचार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते। यही बात उनके अहंकार को चोट पहुंचाती थी।

एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि पूरी कक्षा के सामने नरेंद्र से ऐसा प्रश्न पूछा जाए, जिससे वह उलझ जाएं और उनका आत्मविश्वास टूट जाए। पढ़ाई के दौरान अचानक उन्होंने नरेंद्र को खड़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, "मान लो कि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो। वहां तुम्हें दो बैग पड़े मिलते हैं। एक बैग पूरी तरह धन से भरा हुआ है और दूसरा ज्ञान से। तुम्हें दोनों में से केवल एक बैग उठाने का अवसर मिले, तो तुम किसे चुनोगे?"

कक्षा में सन्नाटा छा गया। अधिकांश विद्यार्थियों को लगा कि इसका उत्तर तो स्पष्ट है। हर कोई सोच रहा था कि नरेंद्र निश्चित रूप से ज्ञान वाला बैग चुनेंगे, क्योंकि ज्ञान को ही सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन नरेंद्र ने बिना एक क्षण गंवाए शांत स्वर में उत्तर दिया, "मैं धन वाला बैग उठाऊंगा।"

उत्तर सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें नरेंद्र को नीचा दिखाने का अवसर मिल गया है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, "मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो ज्ञान वाला बैग चुनता, क्योंकि ज्ञान धन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। धन कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान जीवनभर साथ रहता है।"

पूरी कक्षा की निगाहें अब नरेंद्र पर थीं। सभी यह जानना चाहते थे कि वे अपने उत्तर का बचाव किस प्रकार करेंगे। नरेंद्र ने अत्यंत शांत भाव से प्रोफेसर की ओर देखा और विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, "सर, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रत्येक व्यक्ति वही वस्तु चुनता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है, वह वही प्राप्त करना चाहता है। मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैंने धन वाला बैग चुना।" यह उत्तर सुनते ही पूरी कक्षा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। प्रोफेसर कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके पास नरेंद्र के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। नरेंद्र ने बिना किसी कटुता, अपमान या अभद्रता के केवल एक वाक्य में यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्यों को याद रखने का नाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप तार्किक और सम्मानजनक उत्तर देने की क्षमता का नाम है। यह घटना हमें सिखाती है कि ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण विनम्रता होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तविक ज्ञान है, तो वह कभी अहंकार नहीं करता। वह अपनी बात को दूसरों का अपमान किए बिना भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने उत्तर से न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि आत्मविश्वास और शिष्टाचार साथ-साथ चल सकते हैं। इस प्रसंग का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके उत्तर को सुनकर नहीं करना चाहिए। उसके विचारों की गहराई को समझना भी आवश्यक है। कई बार पहली दृष्टि में कोई उत्तर साधारण या गलत प्रतीत होता है, लेकिन उसके पीछे छिपा तर्क उसे असाधारण बना देता है। नरेंद्र का उत्तर भी ऐसा ही था। उन्होंने धन को ज्ञान से बड़ा नहीं बताया, बल्कि यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति ज्ञान से समृद्ध है, वह धन को जीवन की उपयोगी आवश्यकता के रूप में देख सकता है।

आज का समाज भी इसी प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहा है। लोग अक्सर धन कमाने की दौड़ में अपने व्यक्तित्व के विकास और नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग केवल ज्ञान अर्जित करने तक सीमित रह जाते हैं और जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं। वास्तविक सफलता उन लोगों को मिलती है जो ज्ञान का उपयोग करके धन अर्जित करते हैं और धन का उपयोग समाज, परिवार तथा मानवता के हित में करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के भीतर विचार करने की क्षमता, सत्य को पहचानने की शक्ति, आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। ऐसा ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। जब ज्ञान के साथ चरित्र जुड़ जाता है, तब व्यक्ति केवल सफल नहीं, बल्कि सम्मानित भी बन जाता है।

यह प्रसंग विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में केवल रटकर पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि विद्यार्थी हर विषय को समझें, उस पर विचार करें और अपने भीतर तार्किक सोच विकसित करें। जो विद्यार्थी केवल उत्तर याद करते हैं, वे परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन की कठिन परीक्षाओं में सफल होने के लिए विवेक और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से यही संदेश दिया कि सच्चा शिक्षित वही है, जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, सम्मानपूर्वक अपनी बात कहे और अपने ज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करे।

Border Trade में आया नया मोड़, Myanmar सीमा पर व्यापार शुरू, मगर घोषणा के बावजूद China सीमा पर ट्रेड शुरू नहीं हो पाया

कभी सीमाओं पर पसरा सन्नाटा कहानी का अंत लगता है, तो कभी वही खामोशी नए दौर की सबसे बड़ी दस्तक बन जाती है। सीमाएं जब खुलती हैं तो केवल रास्ते नहीं खुलते, बल्कि बाजारों में रौनक लौटती है, रोजी रोटी की उम्मीदें जागती हैं और सीमावर्ती बस्तियों की धड़कन फिर तेज हो जाती है। इस बार भी सीमाई व्यापार के मंच पर दो अलग अलग दृश्य सामने हैं। एक ओर भारत और म्यांमार के बीच छह वर्षों से बंद पड़ा व्यापारिक रास्ता फिर जीवन से भरने जा रहा है, जबकि दूसरी ओर लिपुलेख के रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापार की पटकथा अभी अधूरी है। वहां बाजार तैयार नहीं होने से कारोबारी इंतजार की अगली कड़ी लिखने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि भारत के सीमाई व्यापार मोर्चे पर एक साथ दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। एक ओर भारत और म्यांमार के बीच पांगसाउ दर्रे से छह वर्ष बाद सीमाई व्यापार दोबारा शुरू होने जा रहा है, जिससे पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार सत्र शुरू होने के बावजूद भारतीय व्यापारियों को अभी भी नए बाजार की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि चीन की ओर से व्यापार व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं होने के कारण कारोबार शुरू होने में देरी हो रही है। दोनों घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि सीमाई व्यापार केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि कूटनीतिक, सामरिक और स्थानीय आजीविका से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भारत और म्यांमार के बीच व्यापार बहाली की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पांगसाउ दर्रे से सीमाई व्यापार छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर शुरू होने जा रहा है। यह व्यापार वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण रोक दिया गया था। इसके बाद महामारी ने भी सीमाई आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर दिया। अब दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद व्यापार दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार व्यापार जुलाई के अंत तक आरंभ होने की संभावना है। इस व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता मुक्त आवाजाही व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग बिना औपचारिक अनुमति के दस किलोमीटर तक एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर व्यापार, छोटे कारोबार, सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध होगा और स्थानीय उत्पादों के लिए नया बाजार भी मिलेगा। साथ ही पांगसाउ मार्ग के फिर खुलने से सबसे अधिक लाभ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले और आसपास के इलाकों को मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों का कहना है कि पिछले छह वर्षों में व्यापार बंद रहने से छोटे व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और स्थानीय बाजारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सीमाई व्यापार फिर शुरू होने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे, बाजारों में चहल पहल लौटेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।

स्थानीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष जोंगखाम मोरांग ने मीडिया से कहा कि व्यापार बहाल होने से क्षेत्र के हजारों छोटे व्यापारियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महामारी और व्यापार बंदी के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठहर गई थीं, अब उनके फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। सीमा चौकी प्रत्येक महीने की दस, बीस और तीस तारीख को संचालित होगी, जिससे नियमित व्यापारिक गतिविधियां सुनिश्चित की जा सकेंगी। दूसरी ओर उत्तराखंड स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार सत्र औपचारिक रूप से शुरू तो हो गया है, लेकिन वास्तविक कारोबार अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि चीन की ओर से नया बाजार और गोदाम पूरी तरह तैयार नहीं हो सके हैं। तिब्बत के तकलाकोट क्षेत्र में नया व्यापारिक केंद्र बनने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते चीनी अधिकारियों ने भारतीय व्यापारियों से कुछ समय और प्रतीक्षा करने को कहा है। हम आपको याद दिला दें कि लिपुलेख मार्ग से व्यापार वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद रोक दिया गया था। इसके बाद लगातार चार वर्षों तक यह मार्ग बंद रहा। इस वर्ष व्यापार फिर शुरू होने की घोषणा से व्यापारियों में उत्साह तो बढ़ा, लेकिन बाजार तैयार नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि बाजार समय पर तैयार हो जाता तो इस बार खच्चरों की जगह सीधे मालवाहक वाहनों से सामान पहुंचाया जा सकता था। इसका सबसे बड़ा कारण धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण का पूरा हो जाना है। हालांकि भारतीय पक्ष ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हम आपको बता दें कि व्यापार सत्र की औपचारिक शुरुआत जून में हो चुकी है और भारतीय व्यापारी जुलाई के शुरू में ही सीमा पार करने की तैयारी में थे। लेकिन इसी दौरान चीनी व्यापारिक साझेदारों की ओर से संदेश मिला कि नया बाजार और आवश्यक ढांचा अभी निर्माणाधीन है। इसलिए व्यापारियों को फिलहाल सीमा पार नहीं भेजा जाए। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नई तिथि की सूचना देने का आश्वासन भी दिया गया है। बहरहाल, दोनों घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सीमाई व्यापार केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचे और दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों से सीधे जुड़ा हुआ है। जहां म्यांमार सीमा पर व्यापार बहाली पूर्वोत्तर के लिए नई आर्थिक संभावनाओं का द्वार खोल रही है, वहीं लिपुलेख पर चीन की धीमी तैयारी यह दिखाती है कि सीमाई व्यापार की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि समय पर आधारभूत सुविधाएं और पारस्परिक समन्वय सुनिश्चित होने पर ही संभव है।

अभियान

अमरनाथ गुफा का अनसुना रहस्य: जब स्वयं शिव ने संसार से छिपाई अमरत्व की दिव्य विद्या

हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपरा के सबसे रहस्यमय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार करके यहां पहुंचते हैं और प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। किंतु अमरनाथ यात्रा का महत्व केवल हिमलिंग के दर्शन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी दिव्य कथा जुड़ी है, जिसे हिंदू धर्म में "अमरकथा" के नाम से जाना जाता है। यह वही कथा है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को जन्म, मृत्यु और अमरत्व का सबसे गुप्त रहस्य बताया था। इस कथा की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान शिव ने इसे इतना गोपनीय माना कि अपने परम प्रिय भक्त नंदी, अपने गले के नाग, यहां तक कि अपने पुत्र भगवान गणेश को भी इसे सुनने की अनुमति नहीं दी। यह प्रसंग केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि त्याग, वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष के गहरे आध्यात्मिक संदेश को भी अपने भीतर समेटे हुए है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के गले में सजी नरमुंडों की माला को बड़े ध्यान से देख रही थीं। उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर भगवान शिव इस माला को क्यों धारण करते हैं और इसमें लगे प्रत्येक मुंड का क्या रहस्य है। उन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्वक भगवान शिव से प्रश्न किया कि इन मुंडों का क्या महत्व है और यह माला कब से उनके गले में है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि इस माला का प्रत्येक मुंड माता पार्वती के एक-एक जन्म का प्रतीक है। जब-जब पार्वती ने नया जन्म लिया, तब-तब उस जन्म की स्मृति स्वरूप उन्होंने अपनी माला में एक और मुंड जोड़ लिया।

यह उत्तर सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने कहा, "यदि मैं बार-बार जन्म लेती हूं और मृत्यु को प्राप्त होती हूं, तो आप सदैव अमर कैसे रहते हैं? आपके अमर होने का रहस्य क्या है?" भगवान शिव जानते थे कि यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। यह सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक था। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि यदि वह इस रहस्य को जानना चाहती हैं, तो उन्हें "अमरकथा" सुननी होगी। यह ऐसी दिव्य विद्या थी, जिसे सुनने वाला जन्म और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता था। इसलिए भगवान शिव ने निश्चय किया कि यह कथा किसी ऐसे स्थान पर सुनाई जाएगी, जहां कोई तीसरा जीव उपस्थित न हो।

इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यह यात्रा केवल एक स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी, बल्कि संसार के समस्त मोह, संबंध और पहचान का क्रमिक त्याग भी थी। मान्यता है कि यात्रा के प्रत्येक पड़ाव का अपना आध्यात्मिक महत्व है और आज अमरनाथ यात्रा का मार्ग भी उन्हीं पवित्र स्थलों से होकर गुजरता है।

सबसे पहले भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन और परम भक्त नंदी को उस स्थान पर छोड़ दिया, जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि "पहलगाम" शब्द का संबंध "बैलगाम" से माना जाता है, अर्थात वह स्थान जहां भगवान शिव ने अपने बैल नंदी को विराम दिया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अहंकार और बाहरी सहारों से मुक्त होना पड़ता है।

इसके बाद भगवान शिव शेषनाग झील पहुंचे और अपने गले में विराजमान नागों को वहीं छोड़ दिया। नाग शक्ति, भय और सांसारिक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इस पड़ाव का संदेश यह है कि आत्मज्ञान की यात्रा में भय और शक्ति के अहंकार का भी त्याग करना आवश्यक है। आज भी शेषनाग झील अमरनाथ यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती है और श्रद्धालु इसे अत्यंत पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं।

आगे बढ़ते हुए भगवान शिव महागुण पर्वत पहुंचे। यहीं उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को रोक दिया। यह प्रसंग अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। भगवान गणेश स्वयं ज्ञान, बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं, फिर भी उन्हें अमरकथा सुनने की अनुमति नहीं मिली। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान गणेश इस ज्ञान के अधिकारी नहीं थे, बल्कि यह दर्शाता है कि कुछ आध्यात्मिक रहस्य ऐसे होते हैं, जिनका अनुभव केवल साधक और गुरु के बीच ही संभव होता है। अमरत्व का ज्ञान बाहरी बुद्धि से नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण और ध्यान की अवस्था से प्राप्त होता है।

इसके बाद भगवान शिव पंचतरणी पहुंचे। यहां उन्होंने पंचमहाभूतों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—का भी त्याग कर दिया। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य का शरीर इन्हीं पांच तत्वों से निर्मित होता है। पंचतरणी में इन तत्वों का त्याग इस बात का प्रतीक है कि आत्मा का परम सत्य शरीर से परे है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता।

इन सभी त्यागों के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस निर्जन गुफा में पहुंचे, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने डमरू, त्रिशूल और अन्य प्रतीकों का भी त्याग किया तथा गहन समाधि में बैठ गए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमरकथा सुनते समय कोई भी अन्य जीव वहां उपस्थित न हो।

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी योगशक्ति से कालाग्नि उत्पन्न की। उन्होंने कालाग्नि को आदेश दिया कि वह गुफा के भीतर और आसपास उपस्थित प्रत्येक जीव-जंतु, कीट-पतंगे और वनस्पति को नष्ट कर दे, ताकि अमरत्व का रहस्य किसी अन्य के कानों तक न पहुंचे। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले मनुष्य को अपने भीतर की सभी सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं और विकारों का अंत करना पड़ता है। जब सब कुछ शांत हो गया, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरकथा सुनाना आरंभ किया। कथा सुनते समय उन्होंने पार्वती से कहा कि वह बीच-बीच में "हूं" कहकर संकेत देती रहें, ताकि उन्हें विश्वास रहे कि वह कथा सुन रही हैं। किंतु लंबी समाधि और हिमालय की शांति के बीच माता पार्वती को हल्की निद्रा आ गई। संयोग से गुफा के एक कोने में कबूतरों का एक जोड़ा उपस्थित था। वे भगवान शिव की कथा ध्यानपूर्वक सुनते रहे और बीच-बीच में "हूं" जैसी ध्वनि निकालते रहे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और उन्होंने पूरी अमरकथा सुना दी।

कथा समाप्त होने पर जब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो निद्रा में हैं, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि किसी अन्य ने यह रहस्य सुन लिया है। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनकी निष्कपटता और संयोग को देखकर उन्हें कोई दंड नहीं दिया, बल्कि अमर होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि वह कबूतरों का जोड़ा आज भी अमर है और समय-समय पर श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा के आसपास दर्शन देता है।

आज भी अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान उन रहस्यमय कबूतरों को देखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी अधिक ऊंचाई, अत्यंत कम तापमान और भोजन की सीमित उपलब्धता वाले क्षेत्र में सामान्य परिस्थितियों में कबूतरों का जीवित रहना कठिन माना जाता है। यही कारण है कि भक्त इन्हें भगवान शिव की अमरकथा का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। आस्था का विषय होने के कारण यह विश्वास आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उतनी ही दृढ़ता से विद्यमान है।

अमरनाथ यात्रा के प्रत्येक पड़ाव का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। पहलगाम त्याग का प्रतीक है, शेषनाग भय और शक्ति के अहंकार से मुक्ति का संदेश देता है, महागुण पर्वत बुद्धि से आगे बढ़कर आत्मानुभूति की ओर संकेत करता है, पंचतरणी पंचमहाभूतों से ऊपर उठने का प्रतीक है और अंततः अमरनाथ गुफा आत्मा के परम सत्य और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार यह पूरी यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। अमरकथा का वास्तविक संदेश केवल शारीरिक अमरता प्राप्त करना नहीं है। सनातन दर्शन के अनुसार शरीर नश्वर है और एक दिन अवश्य समाप्त होता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात के दो प्रमुख कृषि उत्पादों को मिली वैश्विक पहचान, ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को मिला प्रतिष्ठित GI टैग

- GI टैग प्राप्त उत्पादों को सामान्य उत्पादों की तुलना में 20-30 प्रतिशत तक अधिक बाजार मूल्य मिलने की संभावना
- GI टैग से ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को मिलेगी आधिकारिक भौगोलिक पहचान, बढ़ेगी वैश्विक बाजार में विश्वसनीयता और निर्यात की संभावनाएं
- किसानों, उत्पादकों और पारंपरिक कृषि विरासत को मिलेगा कानूनी संरक्षण तथा कृषि आधारित उद्यमों को नए अवसर

गांधीनगर, 13 जुलाई : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' के विज़न को साकार करते हुए तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात अपने पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर गुजरात के प्रसिद्ध मसाला उत्पाद ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भारत सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही दोनों उत्पाद अब वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट भौगोलिक पहचान और आधिकारिक ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे।

गुजरात की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' के विज़न के अनुरूप ऊंझा के जीरा और सौंफ को मिला GI टैग 'गांव से ग्लोबल' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केवल एक सरकारी प्रमाणन नहीं है बल्कि हमारे किसानों की अथक मेहनत, गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन, व्यापारियों के विश्वास और ऊंझा की समृद्ध कृषि परंपरा का सम्मान है। इससे दोनों उत्पादों को विश्व बाजार में विशिष्ट पहचान मिलेगी, वे अपनी अलग ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे और गुजरात के कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई मजबूती मिलेगी।"

GI टैग गुणवत्ता, प्रामाणिकता और भौगोलिक पहचान की आधिकारिक मुहर

GI (भौगोलिक संकेतक) टैग ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जिनकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा विशेषताएं किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। यह टैग वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। GI टैग संबंधित उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, निर्धारित गुणवत्ता मानकों की रक्षा करता है तथा नकली उत्पादों पर प्रभावी रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

GI टैग से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू और निर्यात क्षमता

GI टैग मिलने के बाद ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ दोनों प्रमाणित भौगोलिक ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा बेहतर मूल्य और निर्यात की संभावनाएं मजबूत होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार GI टैग प्राप्त उत्पाद सामान्य उत्पादों की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

सामूहिक प्रयासों से मिला ऊंझा जीरा और ऊंझा वरीयाली को GI टैग

ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इस उपलब्धि में खेतीवाड़ी उत्पन्न बाजार समिति (APMC), ऊंझा, भारत सरकार, गुजरात सरकार के बागायत एवं किसान कल्याण विभाग, सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (SDAU) तथा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), गुजरात सहित विभिन्न संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, व्यापारियों और विभिन्न संस्थाओं के सफल समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस विशेष उपलब्धि पर ऊंझा कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के चेयरमैन श्री दिनेश पटेल ने कहा, "ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को मिला GI टैग ऊंझा के किसानों और मसाला व्यापार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे दोनों उत्पादों की प्रामाणिकता और बाजार विश्वसनीयता को नई मजबूती मिलेगी। वैश्विक स्तर पर इनकी मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।"

भारत की GI सूची में सशक्त हो रही गुजरात की कृषि पहचान

वर्तमान में भारत सरकार की GI रजिस्ट्री में 400 से अधिक उत्पाद पंजीकृत हैं, जिनमें गुजरात के गिर केसर आम, भालिया गेहूं, कच्छी खारेक और अमलसाड़ी चीकू जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों शामिल हैं। अब ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ के भी इस सूची में शामिल होने से गुजरात के GI टैग प्राप्त कृषि उत्पादों की श्रृंखला और सशक्त हुई है। इससे राज्य के कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को नई मजबूती मिलने के साथ किसानों के लिए बेहतर बाजार, मूल्य संवर्धन और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।

पश्चिम रेलवे की डाइविंग टीम ने 79वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप-2026 में जीते 11 पदक

चेन्नई में आयोजित 79वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप-2026 में पश्चिम रेलवे की डाइविंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीतकर पश्चिम रेलवे का गौरव बढ़ाया। टीम ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 2 रजत तथा 6 कांस्य पदक अपने नाम किए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पलक शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल चार पदक जीते। उन्होंने महिला प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत, महिला प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड तथा महिला 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक, जबकि महिला 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा में एक रजत पदक अर्जित किया। ह्रतिका श्रीराम ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल पाँच पदक अपने नाम किए। उन्होंने महिला प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड तथा महिला 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक तथा महिला प्लेटफॉर्म, महिला 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड और महिला 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धाओं में तीन कांस्य पदक जीते।

पुरुष वर्ग में अभिषेक यू ने पुरुष 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड स्पर्धा में एक रजत पदक तथा पुरुष 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड एवं पुरुष 3 मीटर

स्प्रिंगबोर्ड सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धाओं में दो कांस्य पदक जीते। वहीं, निहाल गिराम ने पुरुष प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पश्चिम रेलवे के पदकों की संख्या में एक और उपलब्धि जोड़ी।

पश्चिम रेलवे सभी पदक विजेताओं को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देती है तथा नेशनल चैंपियनशिप में उनके समर्पण, कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संपूर्ण डाइविंग टीम की सराहना करती है।

14 एवं 15 जुलाई, 2026 को केलवे रोड स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक,इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं कवच प्रणाली के कार्य के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित

विरार–दहानू रोड (चरण-I) चौथी लाइन परियोजना के अंतर्गत केलवे रोड स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली एवं कवच के कमीशनिंग कार्य को सुगम बनाने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा 14 एवं 15 जुलाई, 2026 को केलवे रोड स्टेशन पर प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग (Pre-NI) तथा नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को 16.00 बजे से 17.30 बजे तक लिया जाएगा। इस दौरान केलवे रोड स्टेशन पर सिग्नलिंग उपकरणों की पूर्व व्यवस्था, प्वाइंट वायरिंग में संशोधन तथा अन्य संबंधित सिग्नलिंग कार्य किए जाएंगे। इसके पश्चात बुधवार, 15 जुलाई, 2026 को 08.10 बजे से 11.10 बजे तक नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके दौरान केलवे रोड स्टेशन पर नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं कवच प्रणाली का कमीशनिंग कार्य किया जाएगा।

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेन सेवाएं पूर्णतः निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट तथा शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त

कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी रेगुलेट किया जाएगा।

15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली निरस्त ट्रेनें:

1. बोईसर से 08:35 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 61001 बोईसर–वसई रोड मेमू निरस्त रहेगी।
2. दहानू रोड से 09:37 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93012 दहानू रोड–विरार लोकल निरस्त रहेगी।
3. दहानू रोड से 10:22 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93014 दहानू रोड–विरार लोकल निरस्त रहेगी।
4. विरार से 09:30 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93013 विरार–दहानू रोड लोकल निरस्त रहेगी।
5. चर्चगेट से 08:49 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93015 चर्चगेट–दहानू रोड लोकल निरस्त रहेगी।

14 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1. ट्रेन संख्या 22961 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 82901 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
3. ट्रेन संख्या 12954 हजरत निजामुद्दीन–मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
4. ट्रेन संख्या 20932 इंदौर–तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट होगी।
5. ट्रेन संख्या 22956 भुज–बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट रेगुलेट होगी।
6. ट्रेन संख्या 12479 जोधपुर–बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट होगी।
7. ट्रेन संख्या 12489 श्रीगंगानगर–दादर एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1. दहानू रोड से 07:17 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93202 दहानू रोड–चर्चगेट लोकल 25 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 12922 सूरत–मुंबई सेंट्रल फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
3. दहानू रोड से 08:35 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93010 दहानू रोड–बोरीवली लोकल 25 मिनट रेगुलेट होगी।
4. ट्रेन संख्या 22962 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटा रेगुलेट होगी।
5. ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस 40 मिनट रेगुलेट होगी।
6. ट्रेन संख्या 12932 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
7. ट्रेन संख्या 82902 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।
8. ट्रेन संख्या 69139 बोरीवली–वलसाड मेमू 25 मिनट रेगुलेट होगी।
9. चर्चगेट से 07:11 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93009 चर्चगेट–दहानू रोड लोकल 25 मिनट रेगुलेट होगी।
10. ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस–उधना स्पेशल 40 मिनट रेगुलेट होगी।
11. ट्रेन संख्या 19015 दादर–पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

1. 15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ होने वाली ट्रेन संख्या 19002 सूरत–विरार एक्सप्रेस पालघर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
2. 15 जुलाई, 2026 को डोंबिवली से 05:49 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 61002 डोंबिवली–बोइसर मेमू वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
3. 15 जुलाई, 2026 को यात्रा प्रारंभ होने वाली ट्रेन संख्या 59039 विरार–वलसाड पैसेंजर पालघर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

मंडल रेल प्रबंधक ने धोला-पोरबंदर रेलखंड एवं पोरबंदर स्टेशन का किया विस्तृत संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने 11 जुलाई को धोला–पोरबंदर रेलखंड का विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलखंड में संरक्षा व्यवस्था, संरक्षा संबंधी कार्यों की प्रगति, यात्री सुविधाओं, ट्रैक, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली सहित विभिन्न रेल परिसंपत्तियों का गहन निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने पोरबंदर रेलवे स्टेशन का भी विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर हाल ही में पूर्ण हुए यार्ड रीमॉडलिंग कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। उन्होंने नई यार्ड व्यवस्था, परिचालन क्षमता में हुए सुधार, संरक्षा मानकों के अनुपालन तथा कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन परिसंपत्तियों के प्रभावी अनुरक्षण एवं सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने अमृत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित पोरबंदर रेलवे स्टेशन के पूर्ण किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, संरक्षा, सुरक्षा एवं समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएँ उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संरक्षा से संबंधित सभी विकास एवं अनुरक्षण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएँ तथा रेलवे परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं सुरक्षित संचालन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

इस अवसर पर मंडल के शाखाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

वडोदरा मंडल की सराहनीय पहल, रेल सहायकों को नयी वर्दी का वितरण

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा अपने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के कल्याण एवं यात्री सुविधा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुलियों (सहायकों) को नई वर्दियों का वितरण किया।

वडोदरा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा स्टेशन पर कार्यरत 70 रेल सहायकों को वर्दी के सेट वितरित किए। प्रत्येक रेल सहायक को कुल चार शर्टों का एक सेट प्रदान किया गया, जिसमें गर्मियों के लिए तीन लाल शर्टें तथा सर्दियों के लिए एक शर्ट शामिल है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कुलियों को एक समान एवं सुव्यवस्थित पहचान प्रदान करना, उनके सम्मान एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देना तथा यात्रियों के लिए उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाना है। इससे यात्रियों को आवश्यक सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा स्टेशन पर सेवा की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार होगा।

वडोदरा मंडल पश्चिम रेलवे अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी एवं कर्मचारी हितैषी प्रयास करता रहेगा।

गुजरात में आपदा के विरुद्ध नागरिकों को सहायक होने के लिए 'युवा आपदा मित्र स्कीम' अंतर्गत 4,526 युवा प्रशिक्षित

- राज्य के 17 जिलों में 'आपदा मित्रों' को अत्याधुनिक इमर्जेंसी किट से किया गया सज्ज
- जन भागदारी से आपदा प्रबंधन : गुजरात में 50 प्रतिशत महिला भागीदारी के साथ तैयार हो रही है 'आपदा मित्र' की नई पीढ़ी
- आपदा मित्र की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन वर्ष तक 5 साथ रुपए का बीमा कवच

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं मानस सृजति आपदाओं के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा अधिक सुनिश्चित करने के लिए 'आपदा मित्र' प्रोजेक्ट को अधिक वेग दिया गया है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा वर्ष 2016 में भरूच जिले से केवल 200 आपदा मित्रों के साथ शुरू हुई यह योजना हाल में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वटवृक्ष बनकर गाँवों-शहरों में आपदा के समय सेवा दे रही है। हाल में कार्यरत 'युवा आपदा मित्र स्कीम' अंतर्गत राज्य के 17 जिलों के लिए एनसीसी, एनएसएस, एमवाईबी, बीएसएंडजी के कुल 11,850 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के सामने पहले चरण में अब तक लगभग 4,526 युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। इस योजनांतर्गत आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए उनकी 50 प्रतिशत भागीदारी का विशेष लक्ष्य रखा गया है।

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए)-गांधीनगर की विज्ञप्ति में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया गया कि आपदा मित्र सामाजिक स्तर पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के स्थानीय स्वयंसेवकों का समूह है, जो आपदा के समय तत्काल बाचव कार्य करता है। पूर्व में 'अप स्केलिंग ऑफ आपदा मित्र स्कीम' अंतर्गत 17 जिलों के 5,500 आपदा मित्रों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के माध्यम से 12 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि वर्तमान योजना में पहले चरण में एसडीआरएफ तथा मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और अन्य दूसरे चरण में स्पीपा के माध्यम से एडवांस प्रशिक्षण का आयोजन है। इन 17 जिलों में अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, भावनगर, जामनगर, जूनागढ, खेडा, कच्छ, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, तापी, वडोदरा और वलसाड जिलों को शामिल किया गया है।

बचाव कार्य को अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित आपदा मित्रों को 10 हजार रुपए मूल्य की इमर्जेंसी रिस्पॉण्डर किट (ईआरके) दी जाती है। इस किट में लाइफ जैकेट, सलर टॉर्च, फर्स्ट एड किट, हेलमेट तथा 50 मीटर लंबा डिफेंस क्वालिटी रस्सा जैसे 15 अनिवार्य वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा; जिला स्तर पर आपदा के समय बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाने के लिए 19 लाख रुपए मूल्य की ईईईआर किट भी रिजर्व रखी जाती है, जिसमें अद्यतन इनफ्लेटेबल रेस्क्यू बोट, चेन सॉ मशीन, सैटेलाइट जीपीएस तथा वॉकी-टॉकी जैसे संसाधन-उपकरण होते हैं। आपदा मित्र के प्रशिक्षण के निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त चिकित्सा व्यवसायियों तथा सिविल इंजीनियरों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। उम्मीदवार सम्बद्ध जिले का निवासी होना चाहिए और उसने कम से कम कक्षा 7 उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में इस प्रशिक्षण के बाद आपदा मित्र को प्रमाणपत्र, परिचय पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन वर्ष तक 5 लाख रुपए का बीमा कवच भी दिया जाता है।

पूर्व में कोविड-19 महामारी तथा वर्ष 2020 में भारी बाढ़ में भरूच जिले के आपदा मित्रों ने प्रशासन के साथ मिलकर प्रशंसनीय जनसेवा की थी। किसी भी आपदा के समय आम नागरिक या प्रशासन जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) का संपर्क कर आपदा मित्रों की तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि जिला स्तरीय डीईओसी द्वारा आपदा मित्रों की संपूर्ण संपर्क सूची मैंटेन की जाती है। किसी भी आपदा के समय इस केन्द्र द्वारा आपदा मित्रों का संपर्क कर तत्काल उनकी सहायता ली जाती है।

यात्रियों की सुविधा हेतु प्रयागराज–गांधीनगर कैपिटल द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त 13 फेरे

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने गाड़ी संख्या 04111/04112 प्रयागराज–गांधीनगर कैपिटल–प्रयागराज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि का विस्तार करते हुए अतिरिक्त 13 फेरे चलाने का निर्णय लिया है।

पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04111 प्रयागराज–गांधीनगर कैपिटल स्पेशल दिनांक 18 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को कुल 13 फेरों के लिए संचालित की जाएगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 04112 गांधीनगर कैपिटल–प्रयागराज स्पेशल दिनांक 19 जुलाई से 30 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को कुल 13 फेरों के लिए संचालित होगी।

इस विशेष ट्रेन का मार्ग, समय-सारिणी, ठहराव, रेक संरचना, कोच संयोजन तथा अन्य सभी परिचालन संबंधी व्यवस्थाएं पूर्ववत यथावत रहेंगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, सुमेरपुर जवाई

बांध, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी तथा फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व अपनी आरक्षण स्थिति एवं ट्रेन की समय-सारिणी की जानकारी प्राप्त कर लें। इन अतिरिक्त फेरों के लिए बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है।

ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए यात्री राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली (NTES), अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in तथा IRCTC के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मानसून की चाल पड़ी सुस्त, 372 जिलों में बारिश की कमी से बढ़ी चिंता, खेती पर संकट के बीच कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में इस बार मानसून की रफ्तार अपेक्षा से धीमी पड़ने लगी है, जिससे कृषि क्षेत्र और जल संसाधनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा आकलन के अनुसार देश के 372 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि 68 जिले सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी में हैं। मानसून की कमजोर स्थिति का असर अब खरीफ फसलों की बुआई पर भी साफ दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ लगातार समीक्षा शुरू कर दी है और कृषि विभाग से लेकर मौसम विभाग तक आगामी दिनों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 20 जुलाई के बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है, जिससे वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गति धीमी बनी रहेगी। अगले कुछ दिनों तक व्यापक और लगातार बारिश की संभावना कम है। केवल हिमालय से सटे तराई क्षेत्रों और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ही हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच जिन इलाकों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, वहां तापमान और उमस दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

आईएमडी ने मंगलवार के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने तथा निचले इलाकों में जलभराव और भूस्खलन जैसी संभावित परिस्थितियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी गरज-चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने और सावधानी बरतने की

अपील की है। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाली बारिश हो सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फिलहाल मूसलाधार बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यहां केवल हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे उमस से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में किसी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं। राजधानी में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन लगातार भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है।

उत्तर भारत में मानसून का सबसे अधिक प्रभाव हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में पहले से ही भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं, इसलिए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में केवल छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है।

राजस्थान में मानसून की स्थिति फिलहाल कमजोर बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले लगभग एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश नहीं होगी। पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इससे सूखे जैसे हालात में कोई बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है।

पूर्वी भारत में मानसून अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों में नदी-नालों के जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मानसून की सुस्त चाल का सबसे अधिक असर कृषि क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस समय तक लगभग एक करोड़ हेक्टेयर कम क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। बारिश की कमी के कारण कई राज्यों में किसान बुवाई शुरू नहीं कर पाए हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में बुवाई हो चुकी है, वहां फसलों की बढ़वार पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्यों के कृषि विभागों और मौसम विभाग के साथ लगातार समीक्षा शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि यदि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मानसून दोबारा सक्रिय हो जाता है तो खेती की स्थिति में तेजी से सुधार संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष बारिश में देरी के कारण बुआई का सीजन अगस्त के मध्य तक बढ़ सकता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया जुलाई के अंत तक लगभग पूरी हो जाती है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी में नई मौसमी प्रणाली विकसित होने की संभावना है। यदि यह प्रणाली मजबूत होती है तो मानसून को नई ऊर्जा मिलेगी और देश के मध्य, उत्तर तथा पश्चिमी हिस्सों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। इससे वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी होने के साथ-साथ खरीफ फसलों, जलाशयों और भूजल स्तर में भी सुधार आने की उम्मीद है।

फिलहाल देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक ओर कुछ राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में जिले पर्याप्त वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग और केंद्र सरकार दोनों लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले एक सप्ताह की मौसमी गतिविधियां न केवल मानसून की दिशा तय करेंगी, बल्कि इस वर्ष की कृषि, जल उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी उनका सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

नमो एयरपोर्ट से खुलेगा दमन के विकास का नया आसमान, 16 जुलाई से दिल्ली के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान, प्रशासक प्रफुल पटेल ने तैयारियों का लिया जायजा

दमन। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के लिए एक नई विकास यात्रा की शुरुआत अब कुछ ही दिन दूर है। 16 जुलाई से दमन और नई दिल्ली के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल पटेल ने नवनिर्मित नमो एयरपोर्ट, दमन का विस्तृत निरीक्षण कर उद्घाटन उड़ान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और संचालन व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहली उड़ान के संचालन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त और यात्रियों के लिए सुगम बनाई जाएं। निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच क्षेत्र, आगमन और प्रस्थान लाउंज, प्रतीक्षालय, यात्री सुविधाओं, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सेवाओं का विस्तृत जायजा लिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एयरपोर्ट प्रबंधन से तैयारियों की जानकारी प्राप्त की तथा यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि उद्घाटन के दिन यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रफुल पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट के सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा जाए और प्रत्येक व्यवस्था निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा, स्वच्छता, सूचना प्रणाली, यात्री मार्गदर्शन, सामान प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखने पर बल दिया, ताकि पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने कहा कि नमो एयरपोर्ट केवल एक नया हवाई अड्डा नहीं, बल्कि दमन के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। उनके अनुसार इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दमन का सीधा हवाई संपर्क राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली सहित देश के अन्य प्रमुख शहरों से स्थापित होगा, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क का लाभ केवल पर्यटन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे व्यापार, उद्योग, निवेश, सेवा क्षेत्र और स्थानीय रोजगार को भी नई गति मिलेगी। दमन लंबे समय से पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब नियमित हवाई सेवा शुरू होने से यहां निवेश की संभावनाएं और अधिक मजबूत होंगी तथा देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रशासक ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के लोगों को यात्रा के लिए दूरस्थ हवाई अड्डों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों, उद्योग जगत और पर्यटकों को अब सीधे हवाई सेवा का लाभ मिलेगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। गौरतलब है कि नमो एयरपोर्ट का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पण किया गया था। इसके बाद से एयरपोर्ट के नियमित संचालन की तैयारियां तेज कर दी गई थीं। अब 16 जुलाई 2026 से दमन और नई दिल्ली के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने के साथ यह एयरपोर्ट औपचारिक रूप से आम यात्रियों के लिए खुल जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को मजबूत करने की दिशा में यह एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय कारोबारियों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। साथ ही आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक गतिविधियों को भी इससे गति मिलेगी। प्रशासन को उम्मीद है कि नमो एयरपोर्ट के संचालन से दमन राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन और निवेश के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित करेगा। पहली वाणिज्यिक उड़ान के साथ ही दमन के लिए हवाई संपर्क के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास को मिलेगा।

सेमीकंडक्टर क्रांति में राजकोट की बड़ी छलांग, स्वदेशी फैबलेस तकनीक से डेटा सुरक्षा होगी मजबूत, 'आत्मनिर्भर भारत' को मिलेगा नया टेक्नोलॉजी इंजन

राजकोट। गुजरात तेजी से देश के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और अब इस दौड़ में राजकोट ने भी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। अब तक साणंद, धोलेरा और सूरत जैसे शहर राज्य के सेमीकंडक्टर निवेश और औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्र माने जाते रहे हैं, लेकिन अब राजकोट की एक स्वदेशी फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी ने अत्याधुनिक तकनीक के विकास के साथ इस क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा दी हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अगस्त 2026 से बड़े पैमाने पर फैबलेस सेमीकंडक्टर मॉड्यूल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। यह पहल केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सुरक्षा और उच्च तकनीक निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

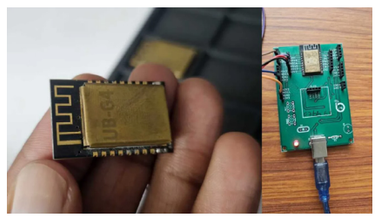

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार, स्मार्ट डिवाइसों की बढ़ती मांग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित तकनीकों के बढ़ते उपयोग के बीच सेमीकंडक्टर उद्योग को देश के भविष्य की आधारभूत आवश्यकता माना जा रहा है। ऐसे समय में राजकोट की इस पहल ने यह संकेत दिया है कि अब देश में केवल बड़े औद्योगिक केंद्र ही नहीं, बल्कि उभरते शहर भी वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं।

कंपनी के संस्थापक एवं निदेशक चिंतन मेहता के अनुसार भारत हर वर्ष एक करोड़ से अधिक फैबलेस सेमीकंडक्टर मॉड्यूल विदेशों से आयात करता है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे विदेशी 'ब्लैक बॉक्स' मॉड्यूल की होती है, जिनमें उपयोगकर्ताओं या संस्थानों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि उनके उपकरणों से प्राप्त डेटा किस देश या किस सर्वर पर संग्रहीत किया जा रहा है। यह स्थिति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के लिहाज से भी गंभीर मानी जाती है।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक से विकसित मॉड्यूल इस समस्या का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करेंगे। भारत में डिजाइन और विकसित किए गए मॉड्यूल के उपयोग से डेटा सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा, साथ ही विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इससे देश का विदेशी मुद्रा व्यय घटेगा और भविष्य में भारतीय तकनीकी उत्पादों के निर्यात को भी नई गति मिलेगी।

कंपनी ने अब तक देशभर में 5,000 से अधिक स्मार्ट डिवाइस स्थापित किए हैं। इन उपकरणों के माध्यम से 40 लाख से अधिक डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से क्लाउड पर संग्रहीत किए जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि उसकी तकनीक डेटा की सुरक्षा, विश्वसनीयता और तेज प्रसंस्करण क्षमता के मामले में आधुनिक वैश्विक मानकों पर आधारित है।

चिंतन मेहता के अनुसार अगस्त 2026 से कंपनी पांच से छह प्रकार के फैबलेस सेमीकंडक्टर मॉड्यूल का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। इन मॉड्यूल का उपयोग औद्योगिक स्वचालन, स्मार्ट शहर परियोजनाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट मीटर, ऊर्जा प्रबंधन, निगरानी प्रणाली, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में किया जा सकेगा। कंपनी का उद्देश्य केवल उत्पाद तैयार करना नहीं, बल्कि 'वर्टिकली एम्बेडेड टू क्लाउड सिस्टम' विकसित करना है, जिसमें हार्डवेयर से लेकर क्लाउड आधारित डेटा प्रबंधन तक संपूर्ण समाधान एकीकृत रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी द्वारा विकसित मॉड्यूल की सबसे बड़ी विशेषता इसका अत्यंत छोटा आकार है। यह मॉड्यूल केवल 18.5 × 29.5 मिलीमीटर का है, लेकिन इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, उच्च दक्षता और कम ऊर्जा खपत जैसी आधुनिक विशेषताएं शामिल हैं। आकार में छोटा होने के कारण इसे विभिन्न स्मार्ट उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में छोटे आकार और अधिक क्षमता वाले ऐसे मॉड्यूल की मांग तेजी से बढ़ने वाली है।

इस परियोजना को केंद्र और गुजरात सरकार की विभिन्न संस्थाओं से भी उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। कंपनी को आई-हब गुजरात के 'सृजन' अनुदान के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये की सहायता मिली है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय (PDEU) और गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से 10 लाख रुपये का अनुदान भी प्रदान किया गया है। यह सहयोग अनुसंधान, उत्पाद विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है।

इतना ही नहीं, जिला उद्योग केंद्र (DIC), राजकोट भी इस परियोजना को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रहा है। एमएसएमई योजना के अंतर्गत कंपनी को बौद्धिक संपदा (आईपी) पंजीकरण, पेटेंट प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे कंपनी को वैश्विक बाजार में अपनी तकनीक प्रस्तुत करने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि फैबलेस सेमीकंडक्टर मॉडल वर्तमान समय में विश्वभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस मॉडल में कंपनियां स्वयं चिप का डिजाइन, अनुसंधान और तकनीकी विकास करती हैं, जबकि वास्तविक निर्माण अत्याधुनिक वैश्विक फाउंड्री में कराया जाता है। इससे कंपनियों को अरबों रुपये के विनिर्माण संयंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे अनुसंधान, डिजाइन, नवाचार तथा नई तकनीकों के विकास पर अधिक संसाधन खर्च कर सकती हैं।

भारत सरकार भी पिछले कुछ वर्षों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र को रणनीतिक महत्व का उद्योग मानते हुए बड़े स्तर पर निवेश और प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। उद्देश्य केवल चिप निर्माण नहीं, बल्कि संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है, जिसमें डिजाइन, अनुसंधान, परीक्षण, पैकेजिंग और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक समाधान विकसित किए जा सकें। राजकोट की यह पहल उसी व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

बिहार में ट्रेन की खिड़की में मोबाइल चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसे 8-9 किलोमीटर तक लटकने के बाद पकड़ा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। बिहार के एक स्टेशन पर खिड़की से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहे एक चोर को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेन चलने ही वाली थी कि मोबाइल चोर ने खिड़की से हाथ अंदर डाला। लेकिन खिड़की के पास बैठे यात्री सतर्क थे और जैसे ही उसका हाथ मोबाइल फोन तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। चोर खिड़की के बाहर लटक गया और अंदर बैठे यात्रियों ने उसका हाथ पकड़ रखा था, तभी ट्रेन चलने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक खिड़की के बाहर लटका हुआ है। वह गिड़गिड़ा रहा है कि कृपया मेरा हाथ छोड़ दें, लेकिन यात्री उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। खगड़िया स्टेशन पर हुई इस घटना में बताया जा रहा है कि लोगों ने चोर को ट्रेन से लटकाकर करीब आठ-नौ किलोमीटर तक घसीटा। अंदर बैठे यात्रियों ने उसका वीडियो भी बनाया और उसमें उसका नाम और पता पूछा। चोर ने अपना नाम छोटू यादव और पिता का नाम पंकज यादव बताया। वह लखमिनिया गांव का रहने वाला था। उसने बचाव में कहा कि वह अपने किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहा था। यात्रियों ने उसका हाथ तब तक पकड़े रखा जब तक वह पास के दूसरे स्टेशन पर नहीं पहुंच गया। यह घटना 9 जुलाई की रात को घटी। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मांजलपुर उपचुनाव में पारदर्शिता पर विशेष जोर, मतदाता अब सीधे चुनाव प्रेक्षकों से मिलकर दर्ज करा सकेंगे शिकायतें और सुझाव

वडोदरा। मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक अब वडोदरा में उपलब्ध रहेंगे। खास बात यह है कि आयोग ने आम मतदाताओं को इन दोनों अधिकारियों से सीधे मुलाकात कर अपनी शिकायतें, सुझाव और चुनाव संबंधी जानकारी साझा करने की सुविधा भी प्रदान की है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि मतदाताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक सुनील कुमार चौधरी वडोदरा स्थित सर्किट हाउस की एनेक्सी बिल्डिंग के प्रेमानंद कक्ष में प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे तक नागरिकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता के पालन, मतदान प्रक्रिया, चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली गतिविधियों तथा अन्य किसी भी चुनाव संबंधी शिकायत या सुझाव को सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

पुलिस प्रेक्षक की भूमिका चुनाव के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी मतदाता को चुनाव प्रचार के दौरान धमकी, दबाव, अवैध गतिविधियों, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास, हिंसा, अवैध हथियारों के उपयोग या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी समस्या की जानकारी मिलती है, तो वह सीधे पुलिस प्रेक्षक को इसकी सूचना दे सकता है। आयोग का उद्देश्य है कि ऐसी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष मतदान का वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

इसी प्रकार निर्वाचन व्यय प्रेक्षक आदित्य शुक्ला भी प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक सर्किट हाउस के 'रवि वर्मा' कक्ष में उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान मतदाता उम्मीदवारों के चुनावी खर्च, प्रचार-प्रसार में धन के उपयोग, निर्धारित व्यय सीमा के संभावित उल्लंघन, नकदी या उपहार वितरण तथा चुनावी खर्च से जुड़ी किसी भी अनियमितता की जानकारी सीधे उन्हें दे सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास चुनावी व्यय से जुड़े दस्तावेज, प्रमाण या अन्य जानकारी उपलब्ध है, तो वह निर्धारित समय पर प्रेक्षक से मिलकर उसे सौंप सकता है।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए व्यय की निगरानी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार के चुनावी खर्च पर आयोग लगातार नजर रखता है ताकि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च या अवैध तरीके से धन के उपयोग जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। ऐसे मामलों में आम नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव केवल प्रशासन या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मतदाता किसी भी प्रकार की अनियमितता देखते हैं और उसकी सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, तो चुनाव को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास, धनबल या बाहुबल के प्रयोग, अवैध चुनावी खर्च, गलत प्रचार, कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों अथवा किसी भी अन्य चुनाव संबंधी शिकायत की जानकारी बिना किसी संकोच के संबंधित प्रेक्षकों तक पहुंचाएं। आयोग का कहना है कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार चुनाव प्रेक्षक पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उनकी रिपोर्ट सीधे भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाती है।

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में माता-पिता के एसआईआर विवरण प्रदान करना अनिवार्य है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के इच्छुक नए आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, अब से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 जमा करने के साथ-साथ आवेदकों को अपने माता-पिता के "विशेष गहन पुनरावलोकन" (यानी एसआईआर) का विवरण देना अनिवार्य होगा।

दिलचस्प बात यह है कि इस नए प्रावधान के लिए मुख्य वैधानिक प्रपत्र-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन यह घोषणा प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से जोड़ी गई है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर प्रपत्र-6 भरता है, तो जब तक वह इस नई घोषणा के कॉलम में माता-पिता के एसआईआर विवरण नहीं भरता, तब तक आवेदन प्रक्रिया सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेगी।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम समेत कई इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। सभी मतदाताओं को मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अब इस नए नियम से पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के लिए माता-पिता के पुराने चुनावी रिकॉर्ड खोजने की प्रक्रिया और भी बढ़ जाएगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पोरबंदर स्टेशन पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन

अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के अंतर्गत पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं जन-जागरूकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 13 जुलाई को चित्रकला (Drawing) एवं निबंध (Essay) प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के नेतृत्व एवं देखरेख में आयोजित किया गया।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रतियोगिताओं में पोरबंदर के पांच प्रतिष्ठित विद्यालयों—महारानी श्रीमती रूपालीबा विद्यालय, नवयुग विद्यालय, बालूबा कन्या विद्यालय, के. बी. जोशी कन्या विद्यालय तथा भावसिंहजी सरकारी हाई स्कूल—के

लगभग 800 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता एवं अभिव्यक्ति कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय रेल के विकास एवं आधुनिकीकरण के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों एवं निबंधों में नवीन सोच, सामाजिक संदेश तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों तथा विजेताओं को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से होने वाले पोरबंदर स्टेशन के लोकार्पण समारोह में 17 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाएंगे।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सफलता में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। मंडल प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों को उनकी उत्कृष्ट सहभागिता के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक, शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।